भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2056

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्मित आवासों की स्थिति

†2056. श्री यूसुफ पठानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के प्रारंभ से लेकर इसके अंतर्गत अब तक स्वीकृत और निर्मित किए गए आवासों का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पूर्ण किए गए आवासों का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में लाभार्थियों द्वारा उनमें कितने आवास बनाए गए हैं; और
(ग) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निर्मित उन आवासों का वर्ष-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है तथा इसकी शुरूवात से अब तक कितने अवासों में रह नही रहे हैं और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय **(**एमओएचयूए**)** दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना**-**शहरी **(**पीएमएवाई**-**यू**)** का कार्यान्वयन कर रहा है**,** जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)**,** साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)**,** स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू के तहत इसकी शुरुआत से अब तक स्वीकृत**,** निर्मित और लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का वर्ष-वार और घटक-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 31.03.2022 थी। इन एएचपी/आईएसएसआर घटक के आवासों को लाभार्थियों को सौंपना समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ उठाया गया एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। आवासों के रिक्त रहने के कारणों में पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता, मौजूदा आजीविका और सोशल नेटवर्क से पलायन या स्थानांतरण की अनिच्छा, लाभार्थी अंशदान में वित्तीय बाधाएँ, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दस्तावेज़ीकरण और आबंटन में देरी शामिल हैं। मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करने और निर्धारित समय- सीमा के भीतर आवास सौंपे जाने को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करके और लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन सुनिश्चित करा कर पीएमएवाई-यू के एएचपी/आईएसएसआर घटकों के तहत आवासों को सौंपने की स्थिति में सुधार करें।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब तक, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.43 लाख आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

*****

दिनांक 11.12.2025 **के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 2056 **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

पीएमएवाई-यू के तहत इसकी शुरुआत से अब तक स्वीकृत, निर्मित और लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का वर्ष-वार और घटक-वार विवरण

वित्त वर्ष	मिशन के अंतर्गत कुल आवास					
	बीएलसी		एएचपी/आईएसएसआर			सीएलएसएस
	स्वीकृत आवास	निर्मित/ सौंपे गए आवास	स्वीकृत आवास	निर्मित आवास	सौंपे गए आवास	स्वीकृत / निर्मित / सौंपे गए आवास
2015-16	1,61,022	1,53,120	3,59,218	3,25,909	2,71,264	5,835
2016-17	4,68,821	4,31,133	1,42,332	1,11,695	76,043	22,607
2017-18	9,94,039	8,98,810	5,59,246	4,15,438	2,44,494	1,12,449
2018-19	14,05,834	12,40,116	3,99,634	2,76,954	1,80,823	4,27,004
2019-20	11,45,038	8,78,066	54,484	38,793	24,143	4,16,403
2020-21	8,73,179	5,63,829	69,242	36,040	15,792	6,05,751
2021-22	10,50,244	7,10,339	98,844	37,298	16,912	4,83,871
2022-23	4,90,984	3,33,930	-	-	-	4,30,300
2023-24	3,86,057	2,55,885	-	-	-	-
कुल	**69,75,218**	**54,65,228**	**16,83,000**	**15,84,141***	**13,20,452***	**25,04,220**

***इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के निर्मित (3.42 लाख) आवास और सौंपे गए (4.90 लाख) आवास शामिल हैं।**